भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3706

सोमवार, 24 मार्च, 2025/03 चैत्र, 1947 (शक)

केएलईएमएस डेटाबेस

3706. श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:
श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:
श्री संजय दिना पाटील:
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:
श्रीमती सुप्रिया सुले:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का नवीनतम केएलईएमएस डेटाबेस देश में रोजगार सृजन की प्रवृत्तियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है और यदि हां, तो रोजगार सृजन के संबंध में उक्त रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं;

(ख) सरकार श्रम बाजार के विभिन्न क्षेत्रों के लिए रोजगार नीतियां तैयार करने और रोजगार सृजन की प्रवृत्तियों की निगरानी करने के लिए केएलईएमएस डाटाबेस का किस प्रकार उपयोग करती है;

(ग) क्या केएलईएमएस के डेटा ने रोजगार, श्रम बाजार सुधारों से संबंधित किन्हीं प्रमुख नीतिगत निर्णयों को प्रभावित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) केएलईएमएस डेटाबेस के अनुसार विशेषकर विनिर्माण, कृषि और सेवा क्षेत्र में रोजगार सृजन की प्रवृत्तियों का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने केएलईएमएस डेटाबेस में प्रदर्शित रोजगार संबंधी आंकड़ों को सत्यापित करने के लिए कोई स्वतंत्र आकलन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार द्वारा केएलईएमएस डेटाबेस द्वारा दी गई जानकारी के आलोक में रोजगार संबंधी चुनौतियों का समाधान करने और सतत रोजगार सृजन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) देश में रोजगार सृजन को बनाए रखने और उसमें तेजी लाने के लिए मौजूद भावी कार्यनीतियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (छ): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रकाशित केएलईएमएस (के: पूंजी, एल: श्रम, ई: ऊर्जा, एम: सामग्री और एस: सेवाएं) डेटाबेस में संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था के **27** उद्योगों को शामिल किया गया है और **27** उद्योगों के रोजगार अनुमान प्रदान किए गए हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश में कुल अनुमानित रोजगार **2017-18** के दौरान **47.49** करोड़ की तुलना में **2023-**

24 के दौरान बढ़कर **64.33** करोड़ (अनंतिम) हो गया है, जो इस अवधि के दौरान **35.46%** की वृद्धि दर्शाता है।

इसके अलावा, कृषि क्षेत्र में जुटे व्यक्तियों की संख्या **2017-18** में **20.02** करोड़ से बढ़कर **2022-23** में **25.30** करोड़ हो गई है। इसी अवधि के दौरान, सेवा क्षेत्र में यह संख्या **16.12** करोड़ से बढ़कर **20.15** करोड़ और विनिर्माण क्षेत्र में **5.47** करोड़ से बढ़कर **6.3** करोड़ हो गई है। इसका ब्यौरा https://m.rbi.org.in/Scripts/PublicationReportDetails.aspx?UrlPage=&ID= 1275. पर देखा जा सकता है।

रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है और यह एक बहु-हितधारक पहल है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदि विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम जैसे प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम आदि कार्यांवित कर रहे हैं, जो पूंजीगत व्यय में वृद्धि के साथ-साथ रोजगार सृजन को बढ़ावा देना चाहते हैं। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण **https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes** पर देखा जा सकता है।

भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देश भर के समाज के सभी वर्गों हेतु विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) आदि के तहत कौशल, पुन: कौशल और कौशल संवर्धन प्रशिक्षण प्रदान करता है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल प्रदान करके भविष्य के लिए सक्षम बनाना है।

इसके अलावा, भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है। दिनांक 28.02.2025 तक, एनसीएस पोर्टल पर 4.7 करोड़ से अधिक रिक्तियां जुटाई गई हैं।

*****